

'राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र में इसी साल शुरू होगा होण्डा के इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया होण्डा के पहले ईवी मॉडल का अनावरण

जयपुर (कांस)। होण्डा की ओर से पहला इलेक्ट्रिक वाहन प्रदेश के टपूकड़ा संयंत्र में बनेगा, जिसका उत्पादन इसी वर्ष शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होण्डा के पहले ईवी मॉडल (होण्डा 0 अल्फा) का अनावरण किया।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में होण्डा के पहले ईवी मॉडल (होण्डा 0 अल्फा) का अनावरण किया।

राजस्थान राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' की तैयारियों के तहत सितंबर 2024 में जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने होण्डा के शीर्ष प्रबंधन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' के आह्वान के समर्थन में राजस्थान में ईवी मॉडल निर्माण एवं निवेश के लिए आमंत्रण किया था। साथ ही, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था। जिसको लेकर होण्डा के प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा एवं ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और रोजगार के सृजन से ज्यादा अक्सर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही, देश के ऑटोमोटिव भविष्य में राज्य की मजबूत भूमिका के लिए निवेशों का समर्थन करती है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं होने एवं इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन यहां होने से अर्थव्यवस्था की गति और तेज होगी। शर्मा ने कहा कि होण्डा टपूकड़ा

संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने जा रही है, जो राजस्थान की प्रभावशाली निवेश नीतियों पर वैश्विक विश्वास का बेहतरीन प्रमाण है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की दिशा में इसके बाद और निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने एवं पर्यावरणीय संतुलन के

संयंत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने जा रही है, जो राजस्थान की प्रभावशाली निवेश नीतियों पर वैश्विक विश्वास का बेहतरीन प्रमाण है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की दिशा में इसके बाद और निवेश बढ़ने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने एवं पर्यावरणीय संतुलन के

होण्डा द्वारा पहले इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिए राजस्थान के टपूकड़ा संयंत्र को चुनना गर्व की बात : भजनलाल शर्मा

साथ औद्योगिक विकास को यात्रा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि होण्डा कम्पनी का राजस्थान से जुड़ाव काफी पुराना है। 2007 में कम्पनी के संयंत्र का शिलान्यास, 2014 में वाहनों का उत्पादन प्रारम्भ हुआ और अब 2026 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले उत्पादन के लिए टपूकड़ा संयंत्र का चयन राजस्थान के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ परिवहन की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु ईवी खरीद पर अनुदान, सिंगल विण्डो सिस्टम के साथ चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जा रही है। साथ ही, 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन को स्क्रेप कराने एवं नए वाहन की खरीद पर

'राजस्थान वाहन स्क्रेपिंग नीति' के तहत छूट भी दी जा रही है।

बैठक के दौरान कम्पनी की ओर से भारत में अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए योजनाएं भी साझा की गईं। साथ ही बताया गया कि यहां उत्पादित मेड इन इंडिया ईवी मॉडल फेरलू बाजार के साथ ही कई देशों में निर्यात किए जाएंगे।

होण्डा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रेसिडेंट एवं सीईओ ताकाशी नाकाजिमा ने बताया कि टपूकड़ा संयंत्र भारत में होण्डा के लिए एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कारों और पुर्जों का निर्माण करता है। अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कम्पनी की ओर से लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने बताया कि होण्डा ने अपने सप्लायर्स और दोषिणा संयंत्र के जरिए राजस्थान में ऑटो और ऑटोपार्ट्स की सप्लाई चैन का एक पुरा इको-सिस्टम तैयार किया है। बैठक में जापान से आए होण्डा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का काम जून तक पूरा करने के निर्देश

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने किया मौका निरीक्षण



नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृथि ने शनिवार को जयपुर में द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन, निदेशक अभियांत्रिकी देवेन्द्र गुप्ता और संबंधित अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृथि ने शनिवार को जयपुर में द्रव्यवती नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने और अशोधित सीवर रोकने के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जयपुर निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम देवेन्द्र गुप्ता, संबंधित अधिशासी अधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया की दहलावास एसटीपी को जाने वाली सीवर लाइन में क्षमता से अधिक सीवर प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त सीवर को डायवर्ट कर द्रव्यवती नदी में प्रवाहित किया जा रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य पर्यटन संचालन है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त सीवर को पूर्व

स्थापित 100 एमएलडी एसटीपी से जोड़ा जा रहा है, ताकि सीवर का समुचित शोधन सुनिश्चित किया जा सके और द्रव्यवती नदी में प्रदूषण रोका जा सके। प्रमुख शासन सचिव ने अधिकाधिकारियों को निर्देश दिए कि यह कार्य जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि राज्य सरकार के मंशानुसूचक द्रव्यवती नदी के जल को स्वच्छ बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सके।

बीएसएनएल के पूर्व अतिरिक्त महाप्रबंधक को दोषमुक्त किया

जयपुर । जयपुर मेट्रो-प्रथम की सीबीआई मामलों की विशेष कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत मामले में बीएसएनएल के तत्कालीन अतिरिक्त महाप्रबंधक बिपिन कुमार रॉय को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्वत राशि की बहामदगी मात्र से ही आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं मान सकते। यह भी जरूरी है कि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्यों के जरिए साबित करे कि आरोपी ने वास्तव में रिश्वत मांगी और उसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था। अभियोजन पक्ष आरोपी का रिश्वत की मांग और उसकी स्वीच्छक स्वीकृति को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर वितरण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में एलपीजी सिलेंडर की वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखने एवं जमाखोरी व कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कोई कमी नहीं है तथा आम उपभोक्ताओं को इसकी निराम्य आपूर्ति जारी है। शर्मा ने कहा कि आम जनता में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर विश्वास बनाए रखा जाए तथा किसी भी प्रकार

गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश

की अनियमितता या दुरुपयोग पाए जाने पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इलेक्ट्रिक नंबर 181, 112 और 14435 पर प्राप्त होनेवाली शिकायतों का भी त्वरित और प्राथमिकता पर समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने अफवाह एवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर निगरानी

रखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एलपीजी उपलब्धता से लेकर आपूर्ति तक की आयोग निरीक्षण की जा रही है तथा ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों की टीमों द्वारा निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। बैठक में राज्य स्तरीय समन्वय ऑयल कम्पनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी के स्टॉक एवं सप्लाई की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री करेंगे 'एक जिला-एक उत्पाद' प्रदर्शनी का शुभारंभ

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान दिवस (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) के अवसर पर प्रदेश में 14-19 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 15-19 मार्च तक राज्य स्तरीय ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही, सभी जिलों में आयोजित होने वाली ओडीओपी प्रदर्शनी के क्रम में जिला स्तरीय प्रदर्शनी 'जयपुर रत्नम्' का आयोजन होगा।

एसीएस होम-एसीएस डीओपी व पंकज चौधरी मध्यस्थता के जरिए सुलझाएं विवाद : कैट

जयपुर । केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जयपुर बेंच ने पदोन्नति मामले में आईपीएस पंकज चौधरी सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह (एसीएस होम) और अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक (एसीएस डीओपी) को कहा है कि वे मध्यस्थता व आपसी बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएं। साथ ही कैट ने तीन सप्ताह का समय देते हुए उम्मीद जताई है कि इस बातचीत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैट ने यह निर्देश पंकज चौधरी के मूल प्रार्थना पत्र पर दिया। कैट ने कहा कि

पक्षकारों से जुड़े कई प्रार्थना पत्र उनके यहां लंबित हैं। प्रार्थी राज्य में एक आईपीएस अफसर है और उनके समक्ष लंबित मामले समान प्रकृति के हैं। कैट की राय है कि इससे कोर्ट और राजस्थान पुलिस प्रशासन का कामती समय बचेंगा जो प्रदेश की जनता के हित में है। एक बेहतरीन पब्लिक सर्विस के अफसरों की सेवाओं का जनता के लिए अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। दरअसल पिछली सुनवाई पर कैट ने राज्य सरकार को कहा था कि वह डीपीसी के तहत उनके बकाया चला रहे प्रमोशन पर

प्रोविजनल तौर पर विचार करे। प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपम अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। प्रार्थी के खिलाफ चल रहे कर्षों के कारण तीन प्रमोशन बकाया हैं। इनमें साल 2018 से जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन और 2021 से सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमोशन शामिल हैं। साल 2023 से उनका डीआईजी रैंक का प्रमोशन रुका हुआ है। जिन मामलों को वजह से उनका प्रमोशन रोका है, उनकी जांच पूरी नहीं हुई है।

हाउसिंग बोर्ड को अवाप्तशुदा जमीन मामले में राहत

माण्डया एन्क्लेव समिति के पक्ष में दिया स्टे आदेश रह

जयपुर (कांस)। गोनर के सिरोली में हाउसिंग बोर्ड की 15 साल पहले अवाप्त की गई करीब 100 करोड़ रुपए की 5.90 हेक्टेयर जमीन से जुड़े मामले में जयपुर मेट्रो-प्रथम की एडीजे कोर्ट-एक ने सिविल कोर्ट के 21 जनवरी 2026 के माण्डया एन्क्लेव योजना विकास समिति के पक्ष में दिया आदेश रद्द कर दिया है।

गोनर के सिरोली में हाउसिंग बोर्ड की 15 साल पहले अवाप्त की गई करीब 100 करोड़ रुपए की 5.90 हेक्टेयर जमीन का प्रकरण

है। इसलिए सिविल कोर्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश गलत है और रद्द किए जाने योग्य है। एडीजे कोर्ट ने यह आदेश हाउसिंग बोर्ड की अपील पर दिया। अधिवक्ता बीसी भारद्वाज ने बताया कि संबंधित जमीन की अवाप्त के लिए हाउसिंग बोर्ड ने 12 अगस्त 2010 को ही अवाप्त नोटिस जारी कर 16 सितंबर 2011 को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। संबंधित भूमि पहले से अधिग्रहण प्रक्रिया में

है और 13 अप्रैल 2017 को अंतिम अवाप्त भी पारित हो चुका है। इसे समिति ने चुनौती नहीं दी है और समिति के पेश पट्टों की वैधता भी विवादित है। ऐसे में सिविल कोर्ट ने समिति के पक्ष में दिया स्टे आदेश गलत है जिसे रद्द किया जाए।

गौरतलब है कि समिति ने 2025 में सिविल कोर्ट में दायर दावे में कहा था कि सिरोली स्थित कई खसरा नंबरों की जमीन पर उनके सदस्यों के प्लॉट हैं। जेडीए से 2013 में भूमि उपयोग परिवर्तन स्वीकृत हुआ और उन्हें प्लॉटों के पट्टे जारी किए थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड 16 सितंबर 2011 की अधिसूचना पर उनकी योजना के भूखंडों पर कब्जा करना चाह रहा है और निर्माण कार्य में रुकावट कर रहा है। सिविल कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 के आदेश से हाउसिंग बोर्ड को जमीन पर दखल करने से रोका था।

गौरतलब है कि समिति ने 2025 में सिविल कोर्ट में दायर दावे में कहा था कि सिरोली स्थित कई खसरा नंबरों की जमीन पर उनके सदस्यों के प्लॉट हैं। जेडीए से 2013 में भूमि उपयोग परिवर्तन स्वीकृत हुआ और उन्हें प्लॉटों के पट्टे जारी किए थे। लेकिन हाउसिंग बोर्ड 16 सितंबर 2011 की अधिसूचना पर उनकी योजना के भूखंडों पर कब्जा करना चाह रहा है और निर्माण कार्य में रुकावट कर रहा है। सिविल कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 के आदेश से हाउसिंग बोर्ड को जमीन पर दखल करने से रोका था।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइप लाइन से तेल चुराने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा

सरगना समेत चार बदमाश एस.ओ.जी. टीम के हथिये चढ़े, एक तकनीकी विशेषज्ञ फरार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की पाइपलाइन से

बदमाशों को हाई-प्रेसर पाइपलाइन पंचकर करने का तकनीकी ज्ञान नहीं था, इसलिए अहमदाबाद से लाखों रुपए का लालच देकर पंकज वाघेला को बुलाया

दिया था। इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक शेर सिंह चौहान ने 5 अगस्त 2023 को सेन्ट्रल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पाइपलाइन में ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ होने के कारण बड़ी दुर्घटना या आग लगने का खतरा भी बना हुआ था, जिससे मामला बेहद गंभीर माना गया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सरगना जितेन्द्र सिंह बर्फ जौतू महाराज ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस चोरी की योजना बनाई थी। चूंकि हाई-प्रेसर पाइपलाइन को पंचकर करने का तकनीकी ज्ञान इनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने

अहमदाबाद (गुजरात) निवासी पंकज वाघेला को लाखों रुपये का लालच देकर बुलाया। वाघेला ने जनरेटर और अन्य उपकरणों की मदद से लक्ष्मण सिंह रावत के खेत में गुजर रही पाइपलाइन को पंचकर कर उस पर वाल्व वेल्ड कर दिया, जो प्रतीत रूप से अचानक हो गया। आरोपियों ने चोरी को छिपाने के लिए वाल्व के चारों ओर मिट्टी के कट्टे भरकर उसे दबा दिया और ऊपर से टैंकर से जुताई कर दी, ताकि किसी को शक न हो।

एक रात जब आरोपी टैंकर लेकर तेल निकालने पहुंचे तो पाइपलाइन में बहाव कम होने के कारण अधिक मात्रा में तेल नहीं निकाल पाए। वापसी के दौरान उनका टैंकर खेत की दलदली जमीन में फंस गया। टैंकर को ट्रेक्टरों की मदद से निकालते समय खेत की सतह पर आए बदलाव और ढीली मिट्टी को देखकर आईओसीएल की गुरत टीम को संदेह हुआ, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। एसओजी ने इस मामले में जितेन्द्र सिंह उर्फ जौतू महाराज (31) निवासी निचला बाडिया, देवेन्द्र सिंह (32) निवासी रामगढ़ सेडोतान, प्रताप शेर सिंह उर्फ शेरू (36) निवासी केसरपुरा, प्रेम सिंह (48) निवासी केसरपुरा को गिरफ्तार किया है और इस मामले में अहमदाबाद निवासी तकनीकी विशेषज्ञ वाघेला फिलहाल फरार है। एसओजी उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और इस तरह की संभावित वारदातों के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।

महिलाओं व बच्चियों तक पहुंचे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई महिला अधिकारिता निदेशालय की समीक्षा बैठक

जयपुर । उपमुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित महिला अधिकारों के संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित उड़ान योजना के तहत बालिकाओं और महिलाओं को दिए जाने वाले निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन आपूर्ति समयबद्धता से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को सचिवालय में महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की।

ही उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं को भी समय पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लाडो प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु योजना का प्रभावी पर्यवेक्षण कराने के

निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु निर्देश दिए।

युवा नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनें : मुख्यमंत्री

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं से आह्वान किया कि उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ें, नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनें। राज्य सरकार हर वर्ग और क्षेत्र के विकास का रोडमैप बनाकर काम कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर, गंगनहर, देवास परियोजना सहित अन्य पैयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं पर प्राथमिकता से काम किया गया है। उद्योगों को भी पर्याप्त पानी देने के लिए काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में 8 हजार 261 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। फिलहाल 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक सम्पूर्ण प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात शनिवार को धांकोटा में अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। उद्योग, व्यापार और रोजगार में वैश्व समाज का योगदान किसी से छुपा नहीं है।

देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चर्म रोग संस्थान एस.एम.एस. हॉस्पिटल में

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । प्रदेशवासियों को जल्द ही राजकीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्म रोग चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चर्म भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। निजी अस्पतालों में लाखों रूपए में होने वाला उपचार यहां आमजन को न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठी ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित इस इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट का जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि लंदन के बाद विश्व का यह दूसरा सबसे एडवांस एवं उत्कृष्ट संस्थान है, जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इस संस्थान में 6 प्रकार की अत्याधुनिक

लेजर मशीनें जैसे डायोड लेजर और फ्रैक्शनल कोबॉन डाई ऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, एनडी-याग लेजर व अलेकजान ड्राइड लेजर स्थापित किये हैं, जो समस्त प्रकार की जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों में काम में लिये जाते हैं। राठी ने बताया कि इस संस्थान में पीआरपी पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां पर हाइड्रो मशीन द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियां हटाने का इलाज भी किया जाएगा। लेजर पद्धति द्वारा सफेद दागों व सोरायसिस का इलाज एवं रेडियो फ्रीक्वेंसी व कायो द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के इलाज की सुविधा भी यहां उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार का एडवांस कॉस्मेटिक उपचार, जो प्राइवेट कॉस्मेटिक संस्थानों में लाखों रुपये में मिलता है, यहां न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। प्रमुख शासन सचिव ने सवाई मानसिंह अस्पताल में नवनिर्मित इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साईंस का भी निरीक्षण किया।

राजस्थान बनेगा एनर्जी ट्रेडिंग का केन्द्र : नागर

जयपुर । भारत का विद्युत क्षेत्र तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा और बदलते बाजार रुझानों के साथ विकसित हो रहा है, जिससे लिटली को कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ा है। इन वारिकियों को समझने के लिए इनेवेटिव एनर्जी रिसोर्स एसोसिएशन और एमएसएस की ओर से 'मार्केट डेरिवेटिव्स व विकसित होता विद्युत क्षेत्र' विषय पर शनिवार को एम.आई.रोड स्थित एक होटल में सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रांभ में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सत्र में वरुंअल माध्यम से जुड़े ऊर्जा मंत्री हारालाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की कीमतों की अतिनिर्भरता को चुनौती के रूप में सामने आई है, ऐसे में डेरिवेटिव मार्केट ने उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को सुरक्षा प्रदान की है।